वैश्विक चुनौतियों से निपटेगा फंड

वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया फंड की भूमिका और उपयोग

पश्चिम एशिया और वैश्विक संकटों से अर्थव्यवस्था सुरक्षित

सीतारमण ने बताया कि यह फंड अचानक पैदा होने वाली आर्थिक झटकों, जैसे पश्चिम एशिया में संकट या अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतार-चढ़ाव, से देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षा कवच देगा. चालू वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार ने 2.81 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की अनुमति मांगी है, जबकि अनुमानित अतिरिक्त आय लगभग 80 हजार करोड़ रुपये होगी. इसके अनुसार वास्तविक अतिरिक्त खर्च केवल 2.01 लाख करोड़ रुपये ही होगा. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष का राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान के भीतर ही रहेगा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत है. इस फंड के साथ-साथ सरकार ने किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी के लिए 19,230 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 23,641 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की मांग की है.

नई दिल्ली, 13 मार्च. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में घोषणा की कि सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक स्थिरीकरण फंड बनाया है. इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों, जैसे पश्चिम एशिया में अचानक उत्पन्न संकटों, से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखना है.

सीतारमण ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 2.81 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की अनुमति मांगी गई है, जबकि अनुमानित अतिरिक्त आय 80 हजार करोड़ रुपये होगी. इस हिसाब से वास्तविक अतिरिक्त खर्च 2.01 लाख करोड़ रुपये ही होगा. फंड का निर्माण सरकार को वित्तीय लचीलापन देगा और वैश्विक आर्थिक झटकों के दौरान त्वरित कदम उठाने की सुविधा प्रदान करेगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान के भीतर ही रहेगा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत है. इसके अतिरिक्त, किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी और गरीब कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त निधि सुनिश्चित की गई है. रक्षा मंत्रालय और अन्य सामाजिक योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त अनुदान का प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक स्थिरीकरण फंड बनाया है. यह फंड विशेष रूप से वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया गया है.

घरेलू बाजार में निरंतर गिरावट

सेंसेक्स में 1470 .50 अंक यानी 1.93 प्रतिशत की गिरावट

निफ्टी 488 .05 अंक यानी 2.06 % गिर कर 23151 .10 अंक पर बंद हुआ

मुंबई, 13 मार्च. ईरान युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में गहराते संकट के बीच भारत के शेयर बाजारों में तेज गिरावट का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा और प्रमुख सूचकांकों में दो प्रतिशत या उससे अधिक की बड़ी गिरावट दर्ज की गयी.

पश्चिम एशिया की स्थिति से ईंधन और मुद्रास्फीति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते आज स्थानीय शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली दिखी. मार्जिन मनी का दबाव बढ़ने से निवेशकों को अपने अल्पकालिक दबाव से निपटने के लिए बिकवाली करनी पड़ रही है. इन सबके सम्मिलित प्रभाव से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 प्रमुख शेयरों वाला निफ्टी-50 कल की तुलना में 488.05 अंक यानी 2.06 प्रतिशत गिर कर 23151.10 अंक पर बंद हुआ. बीएसई30 सेंसेक्स में 1470.50 अंक यानी 1.93 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी और यह 74563.92 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान बीएसई30 शुरू में ही बड़ी गिरावट के साथ 75,444.22 पर खुलने के बाद सुधर कर 75,576.20 तक गया लेकिन लेकिन यह तेजी टिकी नहीं और लगातार गिरावट के बीच एक समय दिन के न्यूनतम 74,454.60 पर पहुंचने के बाद अंत में 74,563.92 पर बंद हुआ.

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए शुरू की पहल

चंडीगढ़, 13 मार्च. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने गुरुवार को हरियाणा में महिलाओं, किसान समूहों के सशक्तीकरण के लिए महिलाओं के नेतृत्व में विकास तथा किसान समूहों को सशक्त बनाने के लिए गुरुवार को कई पहलों की शुरुआत की.

इन पहलों में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत करने, मूल्य संवर्धन क्षमता बढ़ाने और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार को हरियाणा के कैथल और करनाल जिलों में ग्रामीण विकास की इन महत्वपूर्ण पहलों को शुरू किया. एक आधिकारिक अनुसार नाबार्ड के चेयरमैन डॉ. शाजी के.वी. ने कैथल जिले में इनका शुभारंभ करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को समर्थन देना, आजीविका के अवसरों में विविधता लाना और हरियाणा में टिकाऊ ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना है.

नाबार्ड चेयरमैन ने कैथल जिले के फरल गांव में उन्होंने सरस धारा दूध प्रसंस्करण इकाई की आधारशिला भी रखी और विकसित एफपीओ सरसों तेल प्रसंस्करण इकाई तथा उसके बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया. नाबार्ड की ओर से इस गांव में कर्ज सुलभता कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें बैंक, क्रियान्वयन एजेंसियां, एफपीओ प्रतिनिधि और लाभार्थी शामिल हुए, ताकि ग्रामीण उद्यमों के लिए ऋण संपर्क को मजबूत किया जा सके. डॉ शाजी ने जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप के सदस्यों तथा खरखौदा ब्लॉक ऑर्गेनिक एफपीओ और जींद किसान जन निर्माण एफपीओ को स्वीकृति चेक भी सौंपे.

> नाबार्ड चेयरमैन ने करनाल जिले के मंगलोरा गांव में महिला-नेतृत्व वाले एफपीओ हरियाणा अतुल्य नारी शक्ति (हंस) द्वारा स्थापित डेयरी प्रसंस्करण इकाई (बिलोना घी निर्माण) का उद्घाटन किया और महिला सदस्यों व लाभार्थियों से बातचीत की. उन्होंने इन कार्यक्रमों में कहा, हरियाणा ऐसा राज्य बनकर उभरा है जहां प्रगतिशील संस्थान, मजबूत किसान समूह और महिला-नेतृत्व वाले उद्यम ग्रामीण परिवर्तन को आगे बढ़ा रहे हैं. पिछले एक दशक में महिलाओं द्वारा संचालित एफपीओ को बढ़ावा देने और राज्य भर में लगभग 13,000 महिलाओं को संगठित करने के कार्य के साथ नाबार्ड उनके उद्यमशील मार्ग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

पैकेजिंग उद्योग आटोमेशन, मानक सुधारे, सामग्री बचाए : अजय भादू

नई दिल्ली, 13 मार्च. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अजय भादू ने गुरुवार को कहा कि भारतीय पैकेजिंग उद्योग ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से उत्पादकता तथा उत्पाद सुरक्षा को बढ़ाने के साथ सामग्री के व्यर्थ नष्ट होने को कम कर सकता है.

श्री भादू ने कहा कि क्वालिटी और स्टैंडर्डाइज्ड पैकेजिंग भारतीय उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है. वह यहां भारतीय पैकेजिंग संस्थान द्वारा नई दिल्ली में आयोजित पैकेजिंग उद्योग के छठे अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आईएसपीआई 2026 का उद्घाटन कर रहे थे. उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट और टिकाऊ पैकेजिंग पर दिया जोर देते हुए कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, पारिस्थिकी की दृष्टि से स्वस्थ पैकेजिंग तकनीकों की बढ़ती आवश्यकता और उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं के कारण पैकेजिंग इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है. इस सम्मेलन में लगभग 1500 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री प्रतिनिधि, अकादमिक विशेषज्ञ, रिसर्चर्स एवं स्टार्ट-अप शामिल हैं.

सोना-चांदी के दामों में आया उतार-चढ़ाव

1,748 रुपए सस्ता हुआ सोना

8,350 रुपए सस्ती हुई चांदी

नई दिल्ली, 13 मार्च. वैश्विक तनाव और निवेशकों की बदलती रणनीति के बीच शुक्रवार को सोना और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,748 रुपए गिरकर 1.58 लाख रुपए प्रति 1 ग्राम पर आ गया.

इससे एक दिन पहले सोने का भाव 1.60 लाख रुपए था. इसी तरह चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली और एक किलो चांदी 8,350 रुपए सस्ती होकर 2.60 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई. विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा वैश्विक बाजार में अनिश्चितता के कारण निवेशकों का रुझान फिलहाल सोने-चांदी से हटकर नकदी की ओर बढ़ रहा है. इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम होने से भी कमोडिटी बाजार पर दबाव पड़ा है. हालांकि पिछले कुछ महीनों में सोना और चांदी दोनों ने रिकॉर्ड ऊंचाई भी छुई थी, लेकिन हालिया गिरावट ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है.

> वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच शुक्रवार को सोना और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,748 रुपए घटकर 1.58 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. एक दिन पहले यानी 12 मार्च को सोना 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट देखने को मिली. एक किलो चांदी का भाव 8,350 रुपए घटकर 2.60 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गया, जबकि इससे पहले इसका दाम 2.68 लाख रुपए प्रति किलो था.

डॉलर के मुकाबले रुपया और 24 पैसे फिसला

मुंबई, 13 मार्च. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गुरुवार को 25 पैसे और टूट गया. कारोबार की समाप्ति पर डॉलर कल की तुलना में 24 पैसे मजबूत होकर 92.25 रुपये के भाव पर चल रहा था. रुपया इस समय डॉलर के मुकाबले अपने रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर है. कल डॉलर 16 पैसे मजबूत हुआ था. कल का बंद भाव 92.01 रुपये प्रति डॉलर था. कच्चे तेल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में उछाल, घरेलू शेयर बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की निरंतर बिकवाली पिछले कुछ महीनों से मंहगाई दर में बढ़ोतरी से रुपये पर दबाव बना हुआ है.

खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 3 .2 प्रतिशत

नई दिल्ली, 13 मार्च. खाद्य पदार्थों, पर्सनल केयर के सामान और तम्बाकू श्रेणी की वस्तुओं के खुदरा भावों तेजी के चलते देश में खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी माह में बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गयी. यह पिछले 10 महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति का उच्चतम स्तर है.

विश्लेषकों के अनुसार यह वृद्धि मुख्य रूप से पर्सनल केयर उत्पादों, खाद्य पदार्थों और तंबाकू श्रेणी में कीमतें बढ़ने से है. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी खुदरा मूल्य सूचकांक के अनुसार फरवरी 2026 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की खुदरा मुद्रास्फीति क्रमश 3.37 प्रतिशत और 3.02 प्रतिशत थी. प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इस साल फरवरी माह में खाद्य मुद्रास्फीति 3.47 प्रतिशत थी. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ये आंकड़े नई श्रृंखला के तहत दूसरी बार आए हैं पर इस नयी श्रृंखला इस नई श्रृंखला के आधार पर फरवरी 2021 से मुद्रास्फीति के मुख्य दरों का आकलन किया जा सकता है. इससे पहले इससे ऊंची खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2025 में 3.3 प्रतिशत थी. रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिती नायर के अनुसार जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति में 0.47 अंक की वृद्धि में लगभग 0.44 अंक की बढ़ोतरी केवल खाद्य और पेय श्रेणी में महंगाई के चलते हुई है. फरवरी में खाद्य और पेय पदार्थ श्रेणी में मुद्रास्फीति 3.35 प्रतिशत रही, जो जनवरी में 2.1 प्रतिशत थी.

बाजार में अनाज, दालों में तेज, खाद्य तेलों में मिला जुला रुख

नयी दिल्ली, 13 मार्च. दिल्ली थोक जिंस बाजार में गुरुवार को अनाज और दाल-दलहानों में कुल मिला कर तेजी का रुख रहा. खाद्य तेलों में मूंगफली और वनस्पति तेल को छोड़ बाकी तेलों के भाव चढ़े हुए थे.

चीनी और गुड़ बाजार में सामान्य मांग के बीच नरमी का रुख दर्ज किया गया. विदेशी बाजारों में मलेशिया के बुरसा डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम आयल मई वायदा भाव 42 रिंगिट और तेज हो कर 4541 रिंगिट प्रति टन पर पहुंच गया. बुधवार को पाम आयल वायदा 71 रिंगिट की मजबूती के साथ 4,499 रिंगिट प्रति टन के आस पास चल रहा था. अमेरिका सोया तेल मई वायदा भी 1.00 प्रतिशत की तेजी से साथ 67.83 डॉलर प्रति पौंड के स्तर पर बोला जा रहा था. कल यह 67.33 सेंट प्रति पौंड के स्तर पर था. स्थानीय बाजार में औसत दर्ज का चावल 15 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी के साथ 3865.49 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं दड़ा 11 रुपये कड़क हो कर 2808.21 रुपये पर पहुंच गया.

एग्रीनोवेट लि . ने 3 .40 करोड़ का दिया लाभांश

नई दिल्ली, 13 मार्च. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को आज दिल्ली में एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3,39,97,362 का लाभांश अदा किया.

एग्रीनोवेट इंडिया लि., कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम है. यह वितरण निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एग्रीनोवेट इंडिया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सृजनात्मक क्षमता और किसानों की व्यावहारिक आवश्यकता के बीच एक सशक्त पुल का कार्य कर रहा है. कृषि नवाचारों के हस्तांतरण और तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय है. यह आत्मनिर्भर भारत के कृषि लक्ष्य को सशक्त करने वाली पहल है. कार्यक्रम में एग्रीनोवेट इंडिया लि. के अध्यक्ष एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट तथा गैर-सरकारी निदेशक श्री आनंद मोहन अवस्थी उपस्थित थे.

समाचार विशेष

क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों को प्राथमिकता

भाजपा-संघ ने जमीनी मुद्दों को समझने के लिए बनाई रणनीति

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया है. लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर जीत दर्ज करने की कोशिश हुई. दूसरी तरफ विपक्ष ने भाजपा को स्थानीय मुद्दों के आधार पर घेर लिया. सबसे अधिक सवाल सांसदों के क्षेत्र से गायब रहने को लेकर उठे.

स्थानीय मुद्दे भाजपा के चुनावी अभियान से पूरी तरह गायब दिखे. इस कारण स्थानीय स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना उम्मीदवारों को करना पड़ा. कैडर चुनाव के समय उदासीन हो गया और विपक्ष ने यहीं पर पार्टी को घेर लिया. लेकिन, इस हार से सबक लेते हुए भाजपा-आरएसएस ने स्थानीय मुद्दों को अब तरजीह देनी शुरू की है. सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं क्षेत्रीय स्तर की बैठकों में शामिल होकर मूड टटोल रहे हैं.

2027 का चुनाव है अहम- यूपी चुनाव 2027 भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है. ऐसे में भाजपा के साथ-साथ आरएसएस ने भी चुनाव को लेकर तैयारियों को शुरू कर दिया है. जमीनी हकीकत की टोह ली जा रही है. इसको लेकर नए प्रयोग किए जा रही है. यूपी की राजनीति में वर्ष 2014 से भाजपा का बर्चस्व बना हुआ है. 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी जीत मिली और डबल इंजन की सरकार बन गई. हालांकि, यह पहली बार है, जब चुनाव से करीब एक साल पहले संघ और भाजपा की क्षेत्रवार बैठकें शुरू हुई हैं. इन बैठकों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ तक भाग ले रहे हैं.

> **मुद्दों की टटोल रहे जमीनी हकीकत**
>
> प्रदेश स्तर पर पिछले दिनों गरमाए मुद्दों की जमीनी हकीकत को टटोलने की कोशिश शुरू हो गई है. इसमें यूजीसी विवाद सबसे अहम है. इसके नफा-नुकसान को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. दरअसल, संघ-भाजपा के क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय बैठकें लगातार होती रही हैं. इसमें दोनों तरफ के सीनियर पदाधिकारी शामिल होते रहे हैं. हालांकि, यह पहली बार है कि इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ तक शामिल हो रहे हैं. यूपी में संघ की सक्रियता लगातार बढ़ी हुई है. संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले एक साल में प्रदेश के हर हिस्से की यात्रा कर चुके हैं.

हिमाचल में तीसरे मोर्चे की हलचल!

41 नेताओं की गुपचुप बैठक ; नई पार्टी के गठन पर अंदरखाने तैयारियां

शिमला. हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अब तक मुख्य रूप से दो ही दल-भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस-का दबदबा रहा है. लेकिन वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

सूत्रों के अनुसार हाल ही में प्रदेश के करीब 41 नेताओं की एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें नए राजनीतिक विकल्प को लेकर मंथन किया गया. बताया जा रहा है कि इस बैठक में ऐसे कई नेता शामिल थे जो पहले कांग्रेस और भाजपा में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. इन नेताओं के बीच प्रदेश में एक नया राजनीतिक फ्रंट बनाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई.

जानकारी के मुताबिक, संभावित नई पार्टी के गठन को लेकर अंदरखाने तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. सूत्र बताते हैं कि पार्टी का प्रारूप और संविधान तैयार करने का काम चल रहा है और जल्द ही इसके आधिकारिक पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है. राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि इस संभावित तीसरे मोर्चे में पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा और वरिष्ठ नेता खिमीराम सहित कुछ अन्य प्रमुख नेताओं की भूमिका हो सकती है. हालांकि अभी तक इस संबंध में किसी भी नेता की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. यदि यह राजनीतिक पहल आगे बढ़ती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हिमाचल की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रही पारंपरिक मुकाबले को एक नया राजनीतिक विकल्प मिल सकता है.

कांग्रेस से अलग हो मोहम्मद मोकिम ने बनाई पार्टी

भुवनेश्वर. ओडिशा की राजनीति में एक नए दल की एंट्री होने जा रही है. कांग्रेस से अलग हुए वरिष्ठ नेता मोहम्मद मोकिम ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है.

उनकी पार्टी का नाम 'ओडिशा जनता कांग्रेस' रखा गया है, जिसे 8 अप्रैल को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा. मोकिम ने बताया कि पार्टी का शुभारंभ 8 अप्रैल को भुवनेश्वर के प्रदर्शिनी मैदान में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा. इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न हिस्सों से समर्थकों के शामिल होने की संभावना है.उन्होंने कहा कि पार्टी के नाम को लेकर उन्हें भारतीय चुनाव आयोग से मंजूरी मिल चुकी है. अब संगठन के विस्तार और कार्यकर्ताओं को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. मोकिम ने कहा कि नई पार्टी का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर के लोगों से जुड़ना है.

विशेष | राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा

एआईएमआईएम देगी आरजेडी का साथ!

पटना. तेजस्वी यादव 2026 के राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत पक्की करने का प्लान बनाने में लगे हैं. आरजेडी ने एडी सिंह को फिर से अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है.

इस बीच एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान तेजस्वी यादव से मिलने उनके घर गए. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम आरजेडी को अपना समर्थन देगी? जिस पर बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा, हम सिर्फ बात करने आए हैं जो भी होगा, बात मीडिया जरिए आगे बढ़ाई जाएगी. बिहार में पांच राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं. इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेडीयू से राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. एनडीए जहां दावा कर रहा है कि उसके उम्मीदवार सभी पांच सीटों पर जीतेंगे. दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि एडी सिंह की जीत पक्की है. महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक हैं. ऐसे में तेजस्वी यादव जोर शोर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जिसके पांच एमएलए हैं, को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं. यह मीटिंग इसी कोशिश का हिस्सा है.

क्या है राज्यसभा चुनाव का गणित गौरतलब है कि बिहार में एक राज्यसभा उम्मीदवार को जीत दर्ज करने के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत है. विपक्षी गठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं. असदुद्दीन ओवैसी के की पार्टी के पांच और बसपा का एक विधायक इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ एनडीए को भी अपना 5वां उम्मीदवार जितवाने के लिए 3 वोट की दरकार है. ऐसे में अगर एआईएमआईएम विपक्ष का साथ देती है तो एनडीए की टेंशन बढ़ना तय है.

> **अभी सस्पेंस बरकरार**
>
> राज्यसभा चुनाव को लेकर अख्तरुल ईमान और तेजस्वी यादव के बीच क्या कुछ बातचीत हुई इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सियासी हलकों में चर्चा है कि एआईएमआईएम अगर राज्यसभा चुनाव में भाजपा का साथ देती है तो उसकी राजनीति पर असर पड़ सकता है. असदुद्दीन औवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी की 'बी' टीम होने के आरोप लगते रहते हैं. इस लिहाज से देखा जाए तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि वह एडी सिंह का समर्थन करेगी. हालांकि, आखिर में क्या कुछ होता है इसका जवाब चुनाव की तारीख यानी 15 मार्च को मिलेगा.